डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जून, 2023, डिस्पेच दिनांक 1 जून, 2023

| वर्ष 67 | अंक 01 | भोपाल | 1 जून, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

## मध्यप्रदेश में हर गरीब परिवार के पास होगा आवासीय भू-खण्ड : मुख्यमंत्री

**मुख्यमंत्री ने पन्ना में कृषि महाविद्यालय भवन का किया शिलान्यास ● अच्छे कृषि वैज्ञानिक बनकर किसानों के हित में कार्य करें ● पन्ना के विकास के लिये हर संभव प्रयास होंगे**

**भोपाल :** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश की धरती पर हर गरीब परिवार के पास आवासीय भू-खण्ड रहेगा। उन्हें आवासीय भू-अधिकार-पत्र दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि महाविद्यालय के छात्र अच्छे कृषि वैज्ञानिक बन किसानों के हित में कार्य कर मध्यप्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पन्ना जिले के विकास के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान पन्ना में कृषि महाविद्यालय के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महाविद्यालय की छात्रा सेजल की माँग पर महाविद्यालय भवन के साथ छात्रावास भवन बनाने की घोषणा की और कहा कि महाविद्यालय भवन के साथ छात्रावास का निर्माण भी प्रारंभ किया जाये। उन्होंने महाराजा छत्रसाल को प्रणाम कर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को कॉलेज भवन के लिये बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पन्ना की एक लाख 27 हजार लाड़ली बहनों को जून माह से 1000 रूपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम हमाई में नल-जल योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिये और मंगल भवन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम की जनजातीय बस्ती में पात्र गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में पट्टे प्रदान किये जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हमाई ग्राम पंचायत से बरखेड़ा, पहाड़ी खेड़ा होते हुए मजगुआ तक डामर सड़क बनाने के निर्देश दिये।

केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बुंदेलखंड अब पलायन करने वाले लोगों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह विकसित बुंदेलखंड बन गया है। मध्यप्रदेश पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में लगातार अव्वल आ रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों के हित में जो कार्य किये गये हैं, वह अभूतपूर्व हैं।

केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिये कि इस महाविद्यालय की स्थापना दिवस का कार्यक्रम महाराजा छत्रसाल जयंती पर ही किया जाये।

प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को आर्थिक रूप से आजादी दिलाने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने राहत सहायता के नियमों में संशोधन कर किसानों को हुए नुकसान का अधिक मुआवजा दिलाने का कार्य किया है। राज्य सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिये लगातार प्रयास कर रही है।

प्रदेश के खनिज एवं श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पन्ना जिले को कृषि महाविद्यालय की सौगात मिली है। इसके लिये मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ। इस महाविद्यालय में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य होंगे, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और वे अपनी आमदनी को बढ़ा पायेंगे।

संसद सदस्य श्री विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि कृषि महाविद्यालय पन्ना के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉ. प्रमोद मिश्रा ने स्वागत भाषण दिया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

## उन्नत खेती और अधिक उत्पादन के लिये कृषि मेले का लाभ लें : कृषि मंत्री श्री पटेल

**इंदौर में मालवा किसान मेला-2023 का किया शुभारंभ**

**भोपाल :** किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान मेले का अधिक से अधिक लाभ उठायें। उन्नत खेती और अधिक उत्पादन के लिये तकनीकी ज्ञान से स्वयं को समृद्ध करें। उन्होंने कृषि महाविद्यालय इंदौर में मालवा किसान मेला-2023 का शुभारंभ किया। मंत्री श्री पटेल ने मेले में किसानों को कृषि रत्न सम्मान से सम्मानित किया और किसान मेले का अवलोकन भी किया। मेले में श्री दर्शन सिंह चौधरी, श्री महिपाल सिंह, अन्य जन-प्रतिनिधि और कृषक उपस्थित थे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसान मेले में उन्नत खेती करने के तरीके बताये जायेंगे। यहाँ बताया जायेगा कि आधुनिक खेती कैसे करें, गुणवत्तायुक्त उत्पादन कैसे हो, किसानों को अपनी उपज का अधिक से अधिक मूल्य कैसे प्राप्त हो, इन सभी का मेले में बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। किसान भाइयों से आहवान है कि वे मेले का अधिक से अधिक लाभ लें, जिससे उत्पादन वृद्धि में मदद मिल सके।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसान परिवार के बच्चे अब उच्च शिक्षित हो रहे हैं। हम सभी उन्हें खेती के साथ कृषिगत व्यापार और उद्योग के लिये भी प्रोत्साहित करें। सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सतत प्रयासरत है। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। किसानों के अच्छे दिन आये हैं। इसीलिये बेहतर योजनाएँ बना कर लाभान्वित किया जा रहा है। अब सरकार और किसानों के मध्य कोई बिचौलिया नहीं है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हमारा देश गाँव और किसानों का देश है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये तत्कालीन समय में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिये 68 प्रतिशत राशि का प्रावधान बजट में किया था। उन्होंने कहा था कि गाँव को विकास के लिये समुचित राशि उपलब्ध कराना जरूरी है। उनके समय में शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गाँव के विकास के लिये क्रांतिकारी साबित हुई है।

# कृषि के अधो-संरचनात्मक विकास पर दिया जा रहा है जोर : श्री तोमर

## किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये तत्पर है सरकार : कृषि मंत्री श्री पटेल

## विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि महाविद्यालय बालाघाट में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला

**भोपाल :** देश में कृषि के अधो-संरचनात्मक विकास पर निरंतर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को मुनाफे की खेती कर आत्म-निर्भर बनाने के लिये केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रही है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने यह बात विश्व मधुमक्खी दिवस पर बालाघाट में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में कही। प्रदेश के किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सरकार तत्पर होकर कार्य कर रही है। विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधु एक्स-पो का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आयुष एवं जल-संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर 'नानो' कावरे, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित जन-प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि किसानों को आत्म-निर्भर बनाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकार मिल कर निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को आत्म-निर्भर बनाने के लिये उनके उत्पाद की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग द्वारा अधिक से अधिक लाभान्वित करने को 10 हजार एफपीओ बनाये जा रहे हैं। एफपीओ पर केन्द्र सरकार 6 हजार 865 करोड़ रूपये व्यय कर रही है। केन्द्रीय मंत्री ने बालाघाट को विश्व मधुमक्खी दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन के लिये बधाई दी।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिये निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये पंजीयन कराया जा रहा है। इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। प्रदेश में सिंचाई क्षमता को बढ़ा कर 45 लाख हेक्टेयर से बढ़ा कर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किया जा रहा है। किसानों के फसल बीमे की प्रीमियम राशि सरकार द्वारा भरी जा रही है।

### कृषि महाविद्यालय में भवन लोकार्पित

केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर, कृषि मंत्री श्री पटेल एवं अन्य अतिथियों ने बालाघाट के राजा भोज कृषि महाविद्यालय में 80 करोड़ रूपये की लागत से बने भवन, छात्रावास एवं ऑडिटोरियम हॉल का लोकार्पण किया।

### बैलजोड़ी दौड़ का हुआ आयोजन

राजा भोज कृषि महाविद्यालय में बैलजोड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें देश की 170 से अधिक बैलजोड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता को 47 हॉर्स पॉवर, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 42 हॉर्स पॉवर और तृतीय पुरस्कार विजेता को 32 हॉर्स पॉवर का ट्रेक्टर प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 22 विजेता को मोटर-साइकिल प्रदान की गई।

# उत्पादक समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण हेतु दो दिवसीय कार्यशाला
# 7 राज्यों ने की शिरकत, उत्पादों का प्रदर्शन एवं वायर-सेलर मीट हुई

**भोपाल :** केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा ''उत्पादक समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण'' विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला भोपाल में हुई। पहले दिन राष्ट्रीय आजीविका मिशन दिल्ली की टीम द्वारा और राज्यों एवं सहयोगी संस्थाओं के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। दूसरे दिन स्व–सहायता समूहों के उत्पादों का प्रदर्शन तथा वायर-सेलर मीट का आयोजन हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव केन्द्रीय ग्रामीण विकास श्री चरणजीत सिंह, संचालक राष्ट्रीय आजीविका मिशन श्री राघवेन्द्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल, स्टेट मिशन डायरेक्टर आजीविका मिशन गुजरात श्री मनीष बंसल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आजीविका राजस्थान श्री हरदीप सिंह चौपडा, उप निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन श्री रमन बाधवा ने कार्यशाला को संबोधित किया। मध्यप्रदेश सहित 7 राज्यों, सहयोगी संस्थाओं तथा क्रेता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भागीदारी की।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीन दयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निर्धन श्रेणी के परिवारों का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण किया जा रहा है। समूहों से जुडी महिलाओं को आजीविका के एक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये मिशन द्वारा वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण देकर सहयोग किया जाता है।

विभिन्न प्रकार की कृषि एवं गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों के रूप में किये जा रहे कामों से महिलाओं द्वारा अनेकों प्रकार के आजीविका उत्पाद बनाये जा रहे हैं। इन उत्पादों की बिक्री के लिये इन्हें डिजीटल प्लेटफार्म पर लाने के साथ उत्पादों की पहुँच बड़े बाजारों में सक्रिय क्रेताओं तक भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वृहद बाजारों से जुड कर व्यवसाय में वृद्धि होने से समूह सदस्यों की आय में वृद्धि होगी, जिससे वे गरीबी से मुक्ति पाकर समृद्धि की ओर तेजी से आगे बढ सकेंगी।

महिला उत्पादक समूहों से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये वर्तमान में क्या-क्या किया जा रहा है, निकट भविष्य में क्या किया जायेगा, इन बिन्दुओं पर कार्यशाला में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखण्ड एवं तेलंगाना शामिल हुए। केन्द्र सरकार की आधा दर्जन से अधिक सहयोगी संस्थाओं तथा लगभग दो दर्जन क्रेता कंपनियों ने भाग लिया।

## कृषि विकास प्लान का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए

**नर्मदापुरम :** योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य समयसीमा में पूर्ण किया जाए। कृषि एवं कृषि से जुड़े विभागों द्वारा बनाएं गए वार्षिक कृषि विकास प्लान का बेहतर क्रियान्वयन किया जाएं। जिसका लाभ संभाग के किसानों को मिले। यह निर्देश नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर श्री श्रीमन् शुक्ला ने सभी संभागीय एवं जिला अधिकारियों को दिए हैं। कमिश्नर श्री शुक्ला ने आज कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में कृषि से संबद्ध विभागों की योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। कमिश्नर ने मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा कर पात्र मत्स्य पालकों एवं पशुपालकों के शत-प्रतिशत केसीसी के प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बैंक से समन्वय कर केसीसी के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने मत्स्य विभाग अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मत्स्यपालन की विभिन्न गतिविधियों से मत्स्य पालकों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

# सभी ग्रामों में बनेंगी लाड़ली बहना सेनाएँ : मुख्यमंत्री

**आम जनता की जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का उद्देश्य**

**417 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास**

**मुख्यमंत्री धार जिले के गंधवानी में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना महासम्मेलन में हुए शामिल**

**भोपाल :** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बहनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित हैं। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और कार्यों पर निगरानी रखने के लिए लाड़ली बहना सेनाओं की भूमिका को सक्रिय बनाया जाएगा। सभी ग्रामों में लाड़ली बहना सेनाएँ बनेगी। बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों की जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तेजी से क्रियान्वित की जा रही हैं। आगामी 15 अगस्त तक एक लाख शासकीय पदों की भर्ती का कार्य पूर्ण होगा। भर्ती की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री चौहान धार जिले के गंधवानी में लाड़ली बहना महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री गोयल एवं केन्द्रीय टेक्सटाईल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश के पहुँचने पर बहनों ने अगवानी की। जनजातीय समाज द्वारा पारंपरिक रूप से और तीर-कमान भेंट कर स्वागत किया गया। अतिथियों को धार जिले के प्रख्यात बाग प्रिंट के वस्त्र भेंट किये गये। मुख्यमंत्री ने 229 करोड़ 66 लाख रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और 187 करोड़ 76 लाख रूपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। जहाँ विभिन्न संपत्तियाँ महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हो रही हैं वहीं बहनों के कल्याण के लिए कई अभिनव योजनाएँ संचालित हैं। लाड़ली बहना योजना प्रारंभ करने से प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य आसान हुआ है। योजना से मिलने वाली राशि से महिलाओं को छोटे-छोटे खर्चों के लिए अन्य लोगों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा, सहरिया और भारिया के लिए 1000 रूपये मासिक प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई थी। इस राशि से महिलाएँ घर में फल, दूध, सब्जी आदि खरीदने का कार्य कर सकती हैं। लाड़ली बहना योजना भी इस विचार का विस्तार है। इसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों के अलावा सभी बहनों के लिए प्रतिवर्ष 12 हजार रूपये प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 जून से महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। पूर्व सरकार ने संबल योजना को बंद कर दिया और कन्याओं के विवाह के लिए सहायता देना भी बंद हो गया था, जिसे पुनः प्रारंभ किया गया। गरीब वर्ग के हित में सीएम राइज विद्यालय उपयोगी होंगे। ग्रामों में निर्धन तबके के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों की व्यवस्था होना चाहिए। इसी तरह हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पहल भी की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीखो और कमाओ योजना से युवाओं को सहायता देने की जानकारी भी दी। धार जिले में पीएम मित्र पार्क प्रारंभ होने से क्षेत्र में महिलाओं को आसानी से रोजगार उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामों में कन्या के जन्म पर कुछ दशक पूर्व मायूसी देखने को मिलती थी लेकिन अब परिवर्तन आ रहा है। मध्यप्रदेश में बहनें और बेटियाँ सम्मान की पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजनाओं के क्रियान्वयन में जन-सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जन-कल्याण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों, लाड़ली लक्ष्मी से लेकर लाड़ली बहना योजना तक महिला सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना सिर्फ योजना नहीं, एक सामाजिक क्रांति है। महिलाओं के सम्मान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। शराब अहातों को बंद किया जाना, इस कड़ी में लिया गया अहम फैसला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के प्रति धार जिले में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सम्मेलन में इसकी झलक मिली जब "अब जियो लाड़ली बहना, बढ़ चलो लाड़ली बहना..." गायन काफी देर चला।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय वर्ग के गरीबों के लिए पेसा नियम उपयोगी है। धार जिले के सभी विकासखंडों में इसे लागू किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान से समस्याओं के निराकरण के लिए सजग होने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री के आग्रह पर संकल्प लिया कि वे अभियान का लाभ लेंगे।

### निवेश के रास्ते में कोई बाधा नहीं : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रति सोमवार निवेशक की चर्चा के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाता है। धार जिले के पीएम मित्र टेक्सटाईल पार्क से दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाड़ली बहना महासम्मेलन में जनता के बीच जाकर उनका अभिवादन किया। कन्या-पूजन से कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथियों को आम जनता ने उपहार भी प्रदान किए। विशाल पुष्पाहार से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर धार जिले के 13 विकासखंड की बहनों ने जिले की 90 हजार बहनों की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान को पाती (चिट्ठियाँ) सौंपी जिसमें मुख्य मंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद दिया।

केंद्रीय टेक्सटाईल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने कहा कि यह सौभाग्य है कि मुझे मध्यप्रदेश आने का अवसर मिला है। धार जिले में टेक्सटाईल क्षेत्र में अद्भुत कार्य होगा। इसमें महिलाओं की सहभागिता भी होगी। महिलाओं की भागीदारी से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मध्यप्रदेश सजग भी है और गजब भी है। इसे प्रधानमंत्री श्री मोदी भी मानते हैं। पीएम मित्र टेक्सटाईल पार्क से महिलाएँ अधिक सशक्त होंगी। मध्यप्रदेश कई उत्पादों में जीआई टैग प्राप्त कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान के आग्रह पर केंद्र सरकार ने यह पार्क स्वीकृत किया है। इससे क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान का पार्क के लिए जमीन और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर आभार माना। उन्होंने कहा कि हम सब मिल कर तेजी से कार्य करेंगे। पार्क से धार अंचल के विकास को गति मिलेगी और करीब 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

मध्यप्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांसद श्री छतर सिंह दरबार और पूर्व मंत्री सुश्री रंजना बघेल ने भी संबोधित किया। महासम्मेलन में धार जिले की बहनें बड़ी संख्या में शामिल हुई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के गंधवानी में लाड़ली बहना महासम्मेलन के पश्चात पेसा नियम अंतर्गत गठित समितियों के सदस्यों से भी बातचीत की।

धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढ़ा, पूर्व मंत्री श्रीमती रंजना बघेल, मप्र युवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. निशांत खरे, मनोज सोमानी,धार जिला योजना समिति सदस्य श्री जयदीप पटेल, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन श्री मनीष सिंह, इंदौर संभाग कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा, आईजी श्री राकेश गुप्ता, कलेक्टर धार श्री प्रियंक मिश्रा, डीआईजी श्री चंद्रशेखर सिंह सोलंकी, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज सिंह, पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर, पूर्व विधायक श्री करण सिंह पवार, पूर्व विधायक श्री वेलसिंह भूरिया, पूर्व विधायक कालूसिंह ठाकुर सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

## उज्जैन में बनेगा वन स्टॉप मार्केट प्लेस, स्थानीय उत्पादों का होगा प्रमोशन और विक्रय

**प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास ने की समीक्षा**

भोपाल : मध्यप्रदेश में यूनिटी मॉल के माध्यम से वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट, जी.आई. प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस वाणिज्य केंद्र के रूप में उज्जैन शहर में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उज्जैन स्मार्ट सिटी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने उज्जैन नगरपालिक निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के अन्य अधिकारियों के साथ तैयार की जा रही कार्य-योजना की प्रगति की वर्चुअली समीक्षा की। श्री मण्डलोई ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश और प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में प्रस्तावित यूनिटी मॉल के अभिन्यास को तैयार करने के निर्देश दिये। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास के श्री भारत यादव, अपर आयुक्त श्रीमती रूचिका चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

# विकास और जन-कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़े : मुख्यमंत्री श्री चौहान

**महिला सशक्तिकरण मेरी जिंदगी का मिशन**

**स्व-सहायता समूह की बहनें समाज-सुधार का आंदोलन भी चलाएँ**

**मुख्यमंत्री ने समूहों के संकुल स्तरीय संगठन अध्यक्षों से की परिचर्चा**

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं प्रदेश में चल रहे विकास और जन-कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्व-सहायता समूह की बहनों को अपना सहयोगी बनाना चाहता हूँ। प्रदेश में प्रसूति सहायता, संबल, छात्रवृत्ति और प्रधानमंत्री आवास जैसी अनेक योजनाएँ संचालित हैं। जन-सामान्य की समस्याओं तथा लंबित कार्यों के जल्द निराकरण के लिए मध्यप्रदेश जन सेवा अभियान-2 चलाया जा रहा है। अभियान के क्रियान्वयन और लाभ आसानी से समय-सीमा में पात्र लोगों को उपलब्ध कराने में स्व-सहायता समूह की बहनें सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने योजनाओं और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्व-सहायता समूहों को जोड़ने के लिए निश्चित चैनल विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह लोगों की जिंदगी बदलने, उनके चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कान लाने का अभियान है, बहनों से इसमें हरसंभव सहयोग की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्व-सहायता समूहों के संकुल स्तरीय संगठनों की अध्यक्ष बहनों के साथ मुख्यमंत्री निवास में परिचर्चा कर रहे थे।

### अपनी जरूरत का सामान आजीविका स्टोर्स से ही लें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूह की बहनें समाज-सुधार का आंदोलन भी चलाएँ। बच्चों की पढ़ाई, बाल विवाह को रोकने तथा नशा-मुक्ति के लिए समूह अपने स्तर पर गतिविधियों और जागरूकता के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी जरूरत का सामान आजीविका स्टोर्स से ही लें। प्रदेश में आजीविका स्टोर और दीदी कैफे की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश को बढ़ाने और बनाने में आजीविका मिशन महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने सीएम राइज स्कूल, मेधावी विद्यार्थी योजना सहित मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाने की व्यवस्था संबंधी जानकारी भी दी।

### महिलाओं के दर्द से निकली हैं हमारी योजनाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण मेरी जिंदगी का मिशन है। ईश्वर ने बेटा-बेटी को बराबर बनाया, लेकिन ऐतिहासिक कारणों से परिवार और समाज में बेटियों को दोयम दर्जे का माना गया। बहन-बेटियाँ घर-आँगन में काम करने की मशीन बन कर रह गईं। पुरूष प्रधान समाज में न तो उनकी इज्जत थी और न मान-सम्मान था। अबला शब्द महिलाओं का पर्यायवाची बन गया था। बेटियों का जन्म अभिशाप माना जाता था। राज्य सरकार ने इस वेदना और पीड़ादायी स्थिति को बदलने के प्रयास शुरू किए। ऐसे प्रयास किए जिससे बेटी को बोझ नहीं वरदान समझा जाये। जन्म लेते ही बेटी को लखपति बनाने वाली लाड़ली लक्ष्मी योजना हो या विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना, यह प्रयास इसी सोच का परिणाम थे। हमारी योजनाएँ महिलाओं के दर्द से निकली हैं। पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस सहित अन्य शासकीय सेवाओं में महिलाओं की अधिक प्रतिशत में भर्ती और महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई छूट से प्रदेश में सर्वत्र महिला सशक्तिकरण का प्रभाव दिखाई दे रहा है। महिलाएँ, उनको सौंपी गई हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। साथ ही उनकी अपनी पहचान बन रही है। सरपंच पति की पदवी इस सामाजिक क्रांति का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

### लाड़ली बहना योजना से बच्चों के पोषण और घर की हालत में होगा सुधार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के आत्म-सम्मान और आत्म-निर्भरता के लिए ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना आंरभ की गई है। बहनें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, इस उद्देश्य से 10 जून से प्रतिमाह एक हजार रूपए उनके खाते में डाले जाएंगे। यह दिन प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाया जाये। योजना से प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इससे बच्चों का पोषण और घर की हालत दोनों में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भी नव दंपत्ति को दी जाने वाली राशि 49 हजार से बढ़ा कर 51 हजार रूपये की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना और जारी किए जा रहे पट्टे, पति-पत्नी दोनों के नाम जारी किए जाएंगे।

### आजीविका स्टोर की सामग्री पर केन्द्रित विज्ञापन फिल्मों का हुआ प्रदर्शन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परिचर्चा में शामिल 800 संकुल स्तरीय संगठनों की अध्यक्षों का पुष्प- वर्षा कर स्वागत किया और बहनों के साथ दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आरंभ में मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने "आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ते कदम- मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की दस वर्ष की यात्रा" पुस्तक का विमोचन किया। आजीविका स्टार, मध्यप्रदेश आजीविका पोर्टल के लिए विकसित विज्ञापन फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। चर्चा के दौरान महिला अध्यक्षों ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी।

### संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष बहनों से संवाद

- बालाघाट जिले की श्रीमती कुंदा चौधरी क्षेत्र में "रोड रोलर वाली कुंदा" के नाम से प्रसिद्ध हैं। संस्कृत में एमए श्रीमती कुंदा ने बताया कि समूह से जुड़ने पर उन्होंने एमएस डब्ल्यू किया। लोन लेकर दुकान का विस्तार किया, इससे उनकी आय बढ़ी। संकुल के सहयोग और बैंक लोन से समूह ने रोड रोलर खरीदा। इससे अब तक 20 सड़कें बनवा चुकी हैं और समूह को 4 लाख रूपये की आय हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रीमती कुंदा द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ बोले गए संस्कृत श्लोकों की सराहना की।
- कटनी की श्रीमती शकुन पटेल ने बताया कि समूह द्वारा क्षेत्र की बेटियों को रोजगारोमुखी कार्यों का प्रशिक्षण दिलवाया गया। इससे बेटियों को हैदराबाद में रोजगार मिला। जिन बेटियों ने रेल गाड़ी का सपना भी नहीं देखा था, वे बेटियाँ हवाई जहाज से भोपाल से हैदराबाद गई। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र की ये बालिकाएँ आत्म-विश्वास के साथ हैदराबाद में कार्य कर रही हैं।
- झाबुआ की मंजू कटारा ने क्षेत्र की महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए चलाई गतिविधि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके समूह की कोई भी सदस्य अब अंगूठा नहीं लगाती है। समूह द्वारा नारी अधिकार मंच भी संचालित किया जा रहा है।
- राजगढ़ जिले की अनिता दांगी ने बताया कि गाँव का पैसा गाँव में ही रहे, इस उद्देश्य से गाँव में संचालित हो सकने वाले उपयुक्त व्यवसाय के संचालन का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है। साथ ही आर्थिक गतिविधि संचालित करने में हर प्रकार की सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे संकुल स्तर पर करोड़ों का रोटेशन हुआ है।
- शहडोल के संकुल से जुड़ी श्रीमती रेखा बर्मन ने बताया कि महिलाओं को ऑडिट, बुक कीपिंग, रिकार्ड कीपिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब यह महिलाएँ अन्य समूहों के आडिट में भी मदद कर रही हैं।
- आजीविका स्टोर तथा आजीविका मार्ट पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री के प्रचार-प्रसार तथा इनसे खरीददारी को प्रोत्साहित करने के लिए "आजीविका के रंग -खुशियों के संग तथा नई उमंग" नाम से लघु विज्ञापन फिल्में भी बनाई गई हैं।

## शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर 79 हजार 465 क्विंटल से अधिक गेहूँ का हुआ उपार्जन एवं परिवहन

**दतिया।** शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के तहत् जिले में 79 हजार 465 क्विंटल से अधिक गेहूँ का उपार्जन किया गया है। जिसका शतप्रतिशत परिवहन किया जा चुका है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में 79 हजार 465 क्विंटल गेहूँ 97 हजार 955 क्विंटल चना, 660 क्विंटल मसूर, 11 हजार 710 क्विंटल सरसों का उपार्जन शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर किया गया है। जिसमें चना 90 हजार 453 से अधिक क्विंटल, मसूर 649 क्विंटल और सरसों 9 हजार 613 क्विंटल से अधिक का परिवहन किया जा चुका है।

# युवाओं को प्रगति और विकास के नित नये अवसर मिलेंगे : मुख्यमंत्री

**"मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना- युवाओं के लिये लर्न एण्ड अर्न**

**7 जून से संस्थानों और 15 जून से युवाओं का पंजीयन होगा प्रारंभ**

**15 जुलाई से शुरू होंगे प्लेसमेंट**

**भोपाल :**मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं के लिये लर्न एण्ड अर्न की तर्ज पर रोजगार के लिये कौशल सिखाने "मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना" लागू की है। युवाओं को उद्योगों के साथ सर्विस सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण के साथ स्टाईपेंड भी दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा संकल्प है कि युवाओं को बेरोज़गार नहीं रहने देंगे। इस उद्देश्य से युवाओं को रोज़गार के लिए कौशल सिखाने नई योजना लागू की जा रही है। युवाओं को कौशल सीखने के साथ भुगतान भी किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोड़ा जाएगा। नई योजना, युवाओं में क्षमता संवर्धन कर उन्हें पंख देने की योजना है, जिससे वे खुले आसमान में ऊँची उड़ान भर सकें और उन्हें रोज़गार, प्रगति और विकास के नित नए अवसर मिलें।

### प्रशिक्षणार्थियों को स्टाईपेंड

"मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना" में एक लाख युवाओं को 703 चिन्हित क्षेत्रों में दक्ष करने का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। योजना में मध्यप्रदेश के 18 से 29 वर्ष के स्थानीय निवासी 5वीं से 12वीं उत्तीर्ण युवा को 8 हजार रूपये, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500 रूपये, डिप्लोमाधारी को 9 हजार रूपये और स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को 10 हजार रूपये प्रतिमाह स्टाईपेंड दिया जायेगा। राज्य शासन की ओर से निर्धारित स्टाईपेंड की 75 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थियों को डीबीटी से भुगतान की जायेगी। संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टाईपेंड की 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में जमा करानी होगी। प्रतिष्ठान अपनी ओर से निर्धारित राशि से अधिक स्टाईपेंड देने के लिये स्वतंत्र होंगे।

### पंजीयन प्रक्रिया

योजना में ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं का पंजीयन 7 जून से और युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू होगा। युवाओं का प्लेसमेंट 15 जुलाई से होगा। राज्य शासन और ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं के मध्य 31 जुलाई को अनुबंध होगा। योजना में युवाओं को एक अगस्त से प्रशिक्षण दिया जाना शुरू हो जायेगा।

योजना में चिन्हित प्रतिष्ठानों का पेन एवं जीएसटी पंजीयन अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्य-बल के 15 प्रतिशत की संख्या तक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 लोग नियमित रूप से कार्यरत हों, उनके कुल कार्य-बल की गणना ईपीएफ जमा करने के आधार पर की जायेगी। युवाओं को स्टाईपेंड एक वर्ष तक दिया जायेगा।

"मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना" के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति का गठन किया गया है। समिति में वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, श्रम, उच्च शिक्षा के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सदस्य मनोनीत किये गये हैं। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार समिति के सदस्य सचिव होंगे।

### चिन्हित कार्य-क्षेत्र

योजना में युवाओं को प्रशिक्षण के लिये 703 कार्य-क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। इसमें विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रायबल, अस्पताल, रेलवे, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएँ, शिक्षा प्रशिक्षण, सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान आदि को शामिल किया गया है।

# लघु सिंचाई परियोजना से 5 गाँव के सैंकड़ों किसान होंगे लाभान्वित : गृह मंत्री

**दतिया में 15 करोड़ रूपये की परियोजना का भूमि-पूजन**

**भोपाल :** गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दतिया में चहुँओर विकास की गंगा बह रही है। डॉ. मिश्रा ग्राम रिछरा में 14 करोड़ 96 लाख रूपये की लागत की रिछरा-सिरौल नहर लघु सिंचाई परियोजना में हौज पद्धति से बनने वाली नहर के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई परियोजना से 5 गाँव के सैंकड़ों किसान लाभान्वित होंगे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि निर्मित होने वाली लघु सिंचाई परियोजना से किसानों को सीधे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे वे एक वर्ष में 3 फसल ले सकेंगे। किसान हितैषी सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रही है। नहर के बन जाने से किसानों के जीवन-स्तर में सुधार आयेगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने ग्रामीणों से कहा कि नहर निर्माण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिये निरंतर मॉनीटरिंग करें। नहर का संबंध सीधे ग्रामीणों की आजीविका से रहेगा। मंत्री डॉ. मिश्रा ने नहर निर्माण करने वाली एजेंसी के ठेकेदार को हिदायत दी कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने ग्राम रिछरा में ग्रामीणों से संवाद किया। उनकी समस्याएँ सुनी और मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिये।

# मण्डियों को सर्व-सुविधायुक्त बनायेंगे : कृषि मंत्री

**एक करोड़ रूपये के निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास**

**भोपाल :** किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों को सर्व-सुविधायुक्त बनायेंगे। उन्होंने हरदा जिले की कृषि उपज मण्डी टिमरनी में एक करोड़ रूपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते हुए यह बात कही।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मण्डियों के आधुनिकीकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। किसानों को मण्डियों में अधिक से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। केंटीन व्यवस्था के साथ कृषक विश्राम-गृह भी बनाये जा रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने हरदा मुख्य मार्ग से मण्डी गेट तक पहुँच मार्ग के डामरीकरण, सुलभ शौचालय के सामने कांक्रीट रोड, मण्डी प्रांगण में सूचना-केन्द्र एवं हम्माल विश्राम-गृह का निर्माण, केंटीन में अतिरिक्त निर्माण कार्य के साथ कृषक विश्राम-गृह के सामने पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य का भूमि-पूजन किया।

भूमि-पूजन कार्यक्रम में सांसद श्री दुर्गादास उइके, विधायक श्री संजय शाह, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री गजेन्द्र शाह, उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गहलोत, नगरपालिका अध्यक्ष श्री देवेन्द्र भारद्वाज, श्री अमर सिंह मीणा सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

# सतर्कता समिति को सुदृढ़ बनाने के लिये बजट में होगा प्रावधान

**भोपाल :** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली में मिलने वाले गेहूँ एवं चावल न मिलने पर उपभोक्ता इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज करा सकते है। श्री सिंह सोमवार को मंत्रालय में नि:शुल्क खाद्यान्न एवं अन्य विषयों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के लिये तैनात सतर्कता समितियों को सुदृढ़ एवं सशक्तिकृत बनाने के लिये बजट में प्रावधान करने पर विचार किया गया है। अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी, उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल, प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव, संचालक खाद्य श्री दीपक सक्सेना एवं प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री तरूण पिथोड़े उपस्थित थे।

### एन्यूटी मॉडल पर सुसज्जित होंगी दुकानें

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भवनविहिन, जीर्णशीर्ण एवं अपर्याप्त भण्डारण क्षमता वाली उचित मूल्य दुकानों को चिन्हित कर एन्यूटी मॉडल पर नई दुकान सह-गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की लागत से 3500 उचित मूल्य दुकानों का निर्माण होगा। प्रति दुकान के निर्माण पर 13 लाख 50 हजार रूपये की लागत आयेगी। नान द्वारा निविदा के माध्यम से दुकानों का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा, जिसमें 20 प्रतिशत राशि नान एवं 80 प्रतिशत राशि निजी निवेशक द्वारा लगाई जाएगी।

बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा से उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न भण्डार के लिये निर्मित किये जाने वाले गोदाम निर्माण की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17 हजार 700 दुकानों में गोदाम सह भवन निर्माण का प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास को भेजा जायेगा।

### मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में 14 जिलों में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष 38 जिलों में चयन प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके लिये बैंक में 390 प्रस्ताव प्रेषित किये गये है एवं 128 रिक्त सेक्टर्स में पुन: आवेदन आमंत्रित किये गये है।

प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि योजना का लाभ समाज के अंतिम हितग्राही तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रत्येक राशन की दुकान पर हितग्राही को मिलने वाले सुविधाओं पर केन्द्रित आयरन फ्लेक्स लगाये गये है। इन पर उपभोक्ता को मिलने वाले नि:शुल्क एवं स:शुल्क राशन का नाम, मात्रा, प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार का विवरण लिखा गया है। इससे दुकानदारों की मनमानी एवं धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

# किसान भाई खाली खेतों की गहरी जुताई अवश्य करें

सीहोर :किसान भाइयों से कृषि विभाग ने अग्रह किया है कि गेहूं फसलों की कटाई का कार्य हो चुका है एवं खेत खाली है इस परिस्थिति में किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों गहरी जुताई का कार्य कर लेवें। गहरी जुताई कर फसल अवशेषों (नरवाई) को खेत में मिला देने से फसल अवशेष विघटित होकर मिटटी में मिल जाते है।जीवाणु के माध्यम से हयूमस में बदलकर खेत में पौषक तत्व नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर तथा कार्बन शत्व की मात्रा को बढ़ा देते हैं।

प्रत्येक वर्ष एक जैसी फसल ऊगाने से भूमि की ऊपरी सतह से पौषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। गहरी जुताई करने से नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे पलट दी जाती है। जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आने से नीचे छुपे हुये पोषक तत्व मिट्टी के साथ ऊपर आकर पौधों के लिये लाभदायक होते है। भूमि की गहरी जुताई करने से मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाता है, स्थावकाश की मात्रा बढ़ जाती है और जल धारण क्षमता बढ़ जाती है तथा मिट्टी का सूर्यतापीकरण होने से हानिकारक कीट बीमारी के जीवाणु फंगस आदि नष्ट हो जाते है।

आमतौर पर किसान भाई खेत सफाई के उद्देश्य से नरवाई को जला देते है। नरवाई जलने के साथ-साथ खेत की मिट्टी में उपलब्ध लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है एवं पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ आगजनी की घटना आदि से जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि नरवाई को रोटावेटर व कृषि यंत्रों के माध्यम से जुताई कर खेत में मिला दें। फसल अवशेष पर वेस्ट डीकम्पोजर या बायो डायजेस्टर के तैयार घोल का छिड़काव करें। इस प्रकार अवशेष खेतो में विघटित होकर मिट्टी में मिल जायेगे और जीवाणु के माध्यम से ह्यूमस में बदलकर खेत में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जायेगी ।

# किसान खरीफ फसल की बुवाई के पूर्व बीज का अंकुरण कर परीक्षण करे

सीहोर :खरीफ फसल की बुवाई के पूर्व किसान भाई बीज का अंकुरण कर परीक्षण करे , सोयाबीन के 100 दानों का अंकुरण करें, जिसमें 75 से अधिक दाने का अंकुरण होने पर बीज बुवाई के योग्य है। कृषि विकास विभाग ने जिले के किसान भाई से आग्रह किया है कि खरीफ बुआई के पूर्व बीज का अंकुरण आवश्य करें तथा फसल के लिए उर्वरक व्यवस्था समिति या निजी व्यापारी से अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर भंडारित करें, जिससे बुवाई के समय पर कृषकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। किसान भाइयों आपके गांव में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा प्राकृतिक खेती को अपनाने के बारे में जानकारी दी जा रहीं होगी। किसान भाई प्रायोगिक तौर पर प्राकृतिक खेती के घटक को सोयाबीन फसल पर प्रयोगकर परिणाम ले। आगामी फसलों के अधिक रकबे पर प्राकृतिक खेती करें। बीज उर्वरक एवं कीटनाशक क्रय से संबंधित संस्थाओं से पक्के बिल लेवे। फसल विविधीकरण अपनाकर एक से अधिक फसल लेवे ताकि अल्प, अधिक वर्षा होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। साथ ही बीज का चयन करते हुए नवीन किस्म (10 वर्ष के अन्दर) का चयन करें।"

# उपार्जन राशि बैंक खाते में प्राप्ति दिनांक से ही किसानों के खाते में जमा मानी जायेगी

### मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने जारी किया आदेश

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग ने बैंकों से कहा है कि जिस दिन उपार्जन की राशि बैंक के खाते में प्राप्त होती है, उसी दिन संबंधित किसान के खाते में जमा की हुई मानी जाएगी। इस पर बैंक कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगा सकेगी। किसानों को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने की तिथि से प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रि-परिषद की पिछली बैठक में यह मुद्दा आया था कि बैंक खातों में पैसा आने के पश्चात भी समय पर किसानों के खातों में जमा नहीं होता है। इस कारण किसानों को अतिरिक्त ब्याज आने की और डिफाल्टर हो जाने की संभावना रहती है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा इस संबंध में सहकारिता विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था।

**नि:शुल्क खाद्यान्न न मिलने पर सीएम हेल्प लाइन 181 पर करें शिकायत - खाद्य मंत्री श्री सिंह**

# खेत से मिट्टी का नमूना एकत्रित कर किसान भाई मिट्टी परीक्षण कराएं

**सीहोर :** कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि गेहूं फसल की कटाई के उपरांत खेत खाली है और यही समय है, खेत से मिट्टी - का नमूना एकत्रित कर परीक्षण कराने से मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की स्थिति एवं मात्रा का पता चल जाता है, जिससे आगामी खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसल के लिये आवश्यक पौषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। कृषि विभाग ने बताया कि बगैर मिट्टी परीक्षण कराये अनुमान से ही पोषक तत्वों (उर्वरक) की पूर्ति करते हैं, जो कि वास्तविक आवश्यकता से कम या अधिक हो सकती है। जो कि उचित नहीं है।

किसानों से कृषि विभाग द्वारा अपील की है कि वे अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेकर प्रत्येक विकासखण्ड में स्थित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराएं कराए। नि:शुल्क परीक्षण की सुविधा का लाभ लेकर परीक्षण उपरांत प्रयोगशाला द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर प्राप्त करें। जिसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा दर्शायी जाती है। साथ ही आगामी फसल के लिए आवश्यक पौषक तत्वों की अनुशंसा भी की जाती है। किसान भाई जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा विकासखण्ड में स्थित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

# प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उन्नयन एवं नवीन इकाई हेतु कर सकते हैं आवेदन

रायसेन : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग रायसेन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्य खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के (पीएमएफएमई स्कीम) अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विस्तार/उन्नयन या नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना के लिए मौजूदा या नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों पर अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक को प्रसंस्करण इकाई का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार आवेदक के पास स्वयं का भू-स्वामित्व अधिकार की आवासीय/व्यवसायिक भूमि होना आवश्यक है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख का अनुदान प्रावधान है। लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए, शेष राशि बैंक से ऋण के माध्यम से प्राप्त होगी। योजना के तहत सभी प्रकार के प्रसंस्करण इकाईयों पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसमें फल उत्पाद में आम का अचार, नीबू का अचार, जूस, आबंला केंडी, अमरूद जैली, जैम जैली इत्यादी, सब्जी उत्पाद में टमाटर केचप, चटनी, सोस, ड्राय टोमेटो पावडर, मिर्च सोस, आलू/केला चिप्स तथा मसाला उत्पाद में हल्दी, धनियॉ, मिर्च पावडर, लहसुन पेस्ट, सोंठ, इत्यादि की प्रसंस्करण इकाईयों पर अनुदान दिया जाएगा। अनाज उत्पादों में चावल मिल, आटा मिल, दाल मिल, पोहा मिल आदि के साथ ही अन्य उत्पाद पापड, नमकीन, कुरकुरे, ब्रेड, गुड इकाई, पशु आहार, दूध के प्रोडेक्टस (पनीर, मावा, घी इत्यादि), तेल मिल, मांस फ्रीजिंग इत्यादि समस्त प्रकार की प्रसंस्करण इकाई आधारित सूक्ष्म उद्योग पर लाभ की पात्रता होगी। विभाग की योजना का लाभ हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन https:// pmfme.mofpi.gov.in/pmfme esa Applicant Login (PMFME) में कर सकेगें। विभाग की ओर से जिले में रिर्सोस पर्सन नियुक्त किये गए है जो एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जी.एस.टी. आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लायसेंस प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगें। योजना से संबधित अधिक जानकारी हेतु उद्यानिकी विभाग के विकासखण्ड कार्यालय अथवा सहायक संचालक उद्यान रायसेन से सम्पर्क किया जा सकता है।

# मिलेट लगाने के लिए रकबें की वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करें जैविक एवं प्राकृतिक खेती को दे प्राथमिकता कम पानी वाली फसलों का चयन करें

## खरीफ फसल हेतु खाद बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें - कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती राणा कृषि उत्पादन आयुक्त की समीक्षा बैठक संपन्न

**सागर :** मिलेट उत्पादन के लिए रकबें में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। साथ में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्राथमिकता से जागरूक किया जाए। खरीफ फसल हेतु खाद बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती वीरा राणा ने कृषि उत्पादन संबंधी समीक्षा बैठक में दिए।

इस अवसर पर संभागायुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, कलेक्टर श्री दीपक आर्य, ज्वाइंट कमिश्नर श्री अनिल द्विवेदी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.सी. शर्मा सहित कृषि उत्पादन से संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती वीरा राणा ने निर्देश दिए कि सागर संभाग में मिलेट उत्पादन के लिए रकबे में वृद्धि करें। प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।

श्रीमती राणा ने कहा कि खरीफ फसल के लिए अभी से खाद, बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें, जिससे कि खाद बीज के वितरण के समय किसी भी कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि नई फसल के लिए नई तकनीक अपनानी होगी। सुपर सीडर किसान लोन सहित अन्य उपकरणों का प्रयोग करें, जिससे नरवाई जलाने के

कारण हो रही घटनाओं एवं भूमि बंजर होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल में खाद बीज वितरण का रिकॉर्ड को संधारित किया जावे।

श्रीमती राणा ने निर्देश दिए कि सागर संभाग में इस वर्ष 20 से 40 प्रतिशत वर्षा कम होने की भविष्यवाणी की गई है, जिसको देखते हुए कम पानी वाली फसलों का चयन कर उपार्जन का कार्य करें। कृषि उत्पादन आयुक्त की समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग, राज्य सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन संघ की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों के द्वारा दो लाख के ऋण पर ब्याज माफी का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक किसानों से ब्याज माफ करने के लिए आवेदन लिए जाएं।

उन्होंने कहा कि सागर जिले में सोयाबीन की फसल की अपेक्षा उड़द की फसलों के लिए रकबें को बढ़ाएं एवं उपार्जन करें। पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले में 882950 पशुओं के टीकाकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 856064 का टीकाकरण हुआ है जिसको शत-प्रतिशत करें। उन्होंने निर्देश दिए कि लंपी स्किन रोग की रोकथाम के लिए लगातार मॉनिटरिंग करें एवं आवश्यक हो तो तत्काल टीकाकरण कराएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि युवा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय व संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जावे। जिसमें युवाओं को पशुपालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाए। जिले में संचालित मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना अंतर्गत गौशाला संचालन की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले में 33 गौशाला संचालित हो रही हैं, जिनमें बिजली पानी की व्यवस्था की जा रही है। गौशालाओं को अनुदान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आचार्य विद्यासागर योजना के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य एवं पूर्ति की समीक्षा की गई। मुर्रा पाड़ा योजना, नंदी योजना, कुटकुट इकाई योजना के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य पूर्ति एवं खर्च की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में उद्यानिकी विभाग के माध्यम से जिले में कृषि उद्यान की भूमि 736300 हेक्टेयर है, जिसमें से सिंचित एवं उद्यानिकी के रकबें के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि सागर में आम, अमरूद, नीबू, सीताफल, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी सहित समस्त सब्जियों की फसल का उपार्जन किया जाता है। बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत मसाला क्षेत्र, जैविक खेती, प्याज भंडारण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। दुग्ध संघ की समीक्षा बैठक में कार्यरत समितियों के माध्यम से औसत दुग्ध संकलन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि दुग्ध संकलन बढ़ाया जावे, ताकि स्व सहायता समूह के माध्यम से समूह की महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सके।

# कृषक मानसून की पर्याप्त वर्षा होने के बाद ही कपास और सोयाबीन की फसल लगाए

**खण्डवा :** कृषकों को आगामी खरीफ, रबी और जायद में कौन-कौन सी फसलें लेना है इसका अभी समय रहते नियोजन करें तथा फसलों के अधिकाधिक उत्पादन लेने हेतु प्रत्येक स्तर पर समेकित प्रबंधन करें। फसलों के नियोजन अनुसार लगने वाले प्राथमिक आदानों का प्रबंध कर लें। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. आर. आई. सिसोदिया ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों की गहरी जुताई कर खरीफ फसलों की तैयारी आरम्भ करें। उन्होंने बताया कि गहरी जुताई द्वारा भूमि में उपस्थित कीट व्याधियों की सुसुप्तावस्थाएँ एवं खरपतवार नष्ट होते हैं और फसल बोने के बाद इनसे फसल की सुरक्षा होती है। उन्होंने कृषकों से अपील की कि वे अभी से आने वाले समय के लिए कृषि आदानों विशेषकर आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्ता वाले फसलों के बीजों को विश्वसनीय विक्रेता/संस्था द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा किसान भाई खेतों का समतलीकरण, मेड बंदी, सिंचाई नालियों को दुरूस्त करा लें। मानसून की वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व पची हुई गोबर खाद को खेतों में बिखेर दे। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम से कम रखने की जुगत करें तथा जैविक खेती को बढ़ावा दे। समय रहते कीट-व्याधियों का उचित प्रबंधन करें।

कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. सिसोदिया ने बताया कि परामर्श के लिए कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र पहुंचकर मार्गदर्शन कृषक बंधु ले सकते हैं। खरीफ की तैयारी के सन्दर्भ में श्री सतीश परसाई, वरिष्ठ वैज्ञानिक (कीट विज्ञान) ने विशेष तौर पर क्षेत्र/प्रदेश के कृषकों से अपील की कि वे मानसून की पर्याप्त वर्षा होने के बाद ही सोयाबीन कपास आदि की फसल लगाऐं। उन्होंने कृषकों को सलाह दी कि वे शीघ्र या मध्यम अवधि में पकने वाली बी.टी. जातियों का ही चयन करें। उच्च गुणवत्ता वाली किसी भी बी.टी. कपास की प्रजाति को लगाऐं।

उन्होंने कृषकों से आग्रह किया कि वे उन खेतों में इस वर्ष कपास न लगावें जहाँ गत वर्ष उन्होंने कपास लगाया था। श्री परसाई ने कहा कि इन उपायों के अपनाने से आने वाले समय में फसल को कीट व्याधियों के प्रकोप से बचाने या उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखने में मदद मिलेगी।

# विकास प्लान ज़िले की परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाये - कृषि उत्पादन आयुक्त

जबलपुर, कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा रबी 2022-23 की समीक्षा और खरीफ 2024 के कार्यक्रम निर्धारण के संबंध में जबलपुर और सागर संभाग के जिलों के कृषि और कृषि संबध्द विभागों की वीसी के माध्यम से बैठक ली गई। बैठक में दोनों संभागों के कमिश्नर, दोनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, उप संचालक कृषि और कृषि सह संबध्द विभागों के अधिकारी अपने-अपने जिला एनआईसी कक्ष से उपस्थित थे। एपीसी की मीटिंग में कमिश्नर कार्यालय में कमिश्नर श्री अभय वर्मा सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे वहीं कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जयति सिंह सहित कृषि सह संबध्द विभागों के जिला अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा जिले के कृषकों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय में वृध्दि के लिये गतिविधियों का चयन कर जिलेवार जिले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कृषि विकास प्लान तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। फसल विविधीकरण, एकीकृत खेती, नवाचारों, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जबलपुर संभाग के किसानों के लिए अधिक लाभप्रद बनाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल और आयुक्त सह संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले के कृषि विकास प्लान पर चर्चा की गई और जिले की परिस्थिति के अनुसार किसानों की आय में वृध्दि के लिये गतिविधियों का चयन करने के निर्देश दिये गये। बैठक में उर्वरकों एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता होने पर किसानों को सुलभतापूर्वक वितरण किये जाने के निर्देश दिये गये। एपीसी ने हॉर्टिकल्चर का रकबा बढ़ाने और पशुपालन, मत्स्यपालन आदि को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पशुपालन विभाग की समीक्षा में संभाग में सबसे अधिक केसीसी छिंदवाड़ा जिले के द्वारा बनाये जाना पाया गया।

## कोष एवं लेखा अधिकारी/कर्मचारी सहकारी साख संस्था में श्री अखिल कुमार वर्मा अध्यक्ष चुने गये

**श्री देवधर दरबाई तथा श्रीमती विशाखा तुलापुरकर को उपाध्यक्ष बनाया गया**

**इन्दौर :** कोष एवं लेखा अधिकारी/कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित इंदौरके चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए।इसमें श्री अखिल कुमार वर्मा अध्यक्ष चुने गये है। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर श्री देवधर दरबाई तथा श्रीमती विशाखा तुलापुरकर को चुना गया है। संचालक के रूप में श्री हरिश लल्लन शुक्ला, श्री रतनसिंह नर्गेश, श्री समीर कुलकर्णी, श्री मनीष दुबे, श्रीमती अपेक्षा रायसरदार, श्री वरूण रिसोड़कर, श्रीमती अनुपम परमार तथा अमरसिंह परमार चुने गये है। यह निर्वाचन आज प्रशासक श्री आर. एस. ठाकुर एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्री के. एल. दवे की उपस्थिति में हुआ।

## स्व सहायता समूहों की महिलाओं के आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते कदम

बुरहानपुर : मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला बुरहानपुर अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा स्कूली बच्चों के गणेवश सिलाई का कार्य किया जा रहा है। परियोजना प्रबंधक श्रीमति संतमति खलको ने जानकारी देते हुए बताया कि, पावरलूम से अभी तक कुल 38150 गणवेशों का कपडा प्राप्त हुआ है। जिसमें समूहों द्वारा 6600 गणवेश तैयार कर 2464 गणवेशों का वितरण किया गया है। कुल 39 स्व सहायता सूमहों की महिलाओं द्वारा गणवेश सिलाई का कार्य किया जा रहा है। समूह की महिलाओं द्वारा निरंतर आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है।

## मछली पालन हेतु नायलोन जाल के व्यवसाय में तराशा भविष्य

**बुरहानपुर :** मछली पालन हेतु नायलोन जाल के व्यवसाय में तराशा अपना भविष्य, साक्षी शर्मा फर्म से फिश नेट गियर कंपनी बनाकर कार्य कर रही है। संचालक श्री शिशिर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि मछली का नायलोन जाल बनाने का कार्य फर्म द्वारा कुशल कारीगरों के माध्यम से तैयार किया जाता है, ताकि मछली उत्पादकों को बेहतर क्वालिटी का नायलोन जाल प्राप्त हो सकें। वे बताते है कि मछली के नायलोन जाल बनाने का कार्य केवल बुरहानपुर जिले में हो रहा है। कपड़ा बनाने के लिए कच्चा मटेरियल भावनगर व सूरत से मंगवाया जाता है। जिसके बाद धागे को फैक्ट्री विभिन्न प्रक्रियाएं पूण करते हुए जाल तैयार किया जाता है। तैयार मछली के जाल को मुम्बई, कोलकता इत्यादि शहरों में जहां मछली मार्केट अधिक होता है, वहां डिमांड के अनुसार भेजा जाता है। उन्होंने मछली उत्पादनकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि आपको मछली का जाल खरीदने के लिए कही भटकने की जरूरत नहीं है। हमारी फर्म में आकर सस्ती दरों से मछली का जाल खरीद सकते है। उन्होंने बताया कि उक्त व्यवसाय स्थापित करने में मत्स्योद्योग सहायक संचालक श्री ए.एस.भटनागर मार्गदर्शक रहे। इसके लिए मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि मेरा कारखाना तीन करोड़ की लागत से बना है और उद्योग विभाग से अनुदान भी मिला है। यदि शासन द्वारा सहयोग दिया जाता है तो नायलोन धागा निर्माण का कार्य भी बुरहानपुर में प्रारंभ किया जा सकता है।

# गोदाम और बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापना से खुश है किसान

**सतना :** उचेहरा विकासखण्ड के ग्राम पिपरोखर में लगभग 13 वर्ष से बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रही जैतपाल सिंह बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पिपरोखर के संलग्न किसान बीज गोदाम और बीज प्रसंस्करण इकाई की सुविधा से अब बेहद प्रसन्न है। शासन की एसएमएसपी योजना के तहत इन्हें 500 मे. टन क्षमता का बीज गोदाम और बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। योजना के तहत संस्था को 60 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता गोदाम बनाने और मशीनरी खरीदने के लिए दी गई है। संस्था के अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह और सचिव रामगोपाल कुशवाहा ने बताया कि संस्था की स्थापना 2010 में हुई थी। तब से संस्था इस क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं का गोदाम नहीं होने और बीज प्रसंस्करण सुविधा नहीं होने से संस्था का आधा बजट भण्डारण परिवहन एवं बीज प्रसंस्करण में ही खर्च हो जाता था। अब समिति की आय बढ़ने से सदस्य किसानों को लाभांश भी मिलेगा।

# सफलतापूर्वक मशरुम उत्पादन कर रहीं दीदियों के बीच पहुँचे सांसद श्री शेजवलकर

**कहा आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिये हर संभव मदद दिलायेंगे**

**ग्वालियर :**स्व-सहायता समूहों में संगठित होकर आत्मनिर्भरता की मिसाल स्थापित कर रहीं समूहों की दीदियों के प्रोत्साहन के लिए सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ग्राम विजयगढ़ पहुँचे। जिले की ग्राम पंचायत सिरोली के ग्राम विजयगढ़ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित 9 स्व-सहायता समूहों की 60 दीदियाँ सफलतापूर्वक मशरूम उत्पादन कर अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर रही हैं। साथ ही वे अन्य आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ी हैं।

सांसद श्री शेजवलकर समूहों की दीदियों को भरोसा दिलाया कि स्व-सहाया समूहों द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने में हर संभव मदद दिलाई जायेगी। उन्होंने समूहों की दीदियों से विस्तार से चर्चा की। दीदियों का कहना था कि मशरूम के हर बैग से उन्हें 1500 से 2000 रूपए तक की आमदनी हो जाती है। उत्पादन बढ़ने पर हमने ड्रायर, कैनिंग व पैकिंग पाउडर इत्यादि की मशीनें भी लगा ली हैं। समूहों द्वारा मशरूम से पाउडर, अचार व ड्राई मशरूम भी बाजार में बेचने का काम किया जाता है। दीदियों ने इस कारोबार को विस्तार देने के की आशा व्यक्त करने पर सांसद श्री शेजवलकर ने भरोसा दिलाया कि आप सब चिंता न करें, सरकार और उनकी ओर से इस काम के लिये हर संभव मदद उपलब्ध कराई जायेगी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।